

## RTI जवाबदेही रपिोर्ट कार्ड

### प्रलिमिंस के लयि:

सूचना का अधकिार (RTI) अधनियिम, केंद्रीय सूचना आयोग, SIC, सतरक नागरकि संगठन ।

### मेन्स के लयि:

सूचना का अधकिार (RTI) अधनियिम, पारदर्शति और जवाबदेही ।

## चर्चा में क्यों?

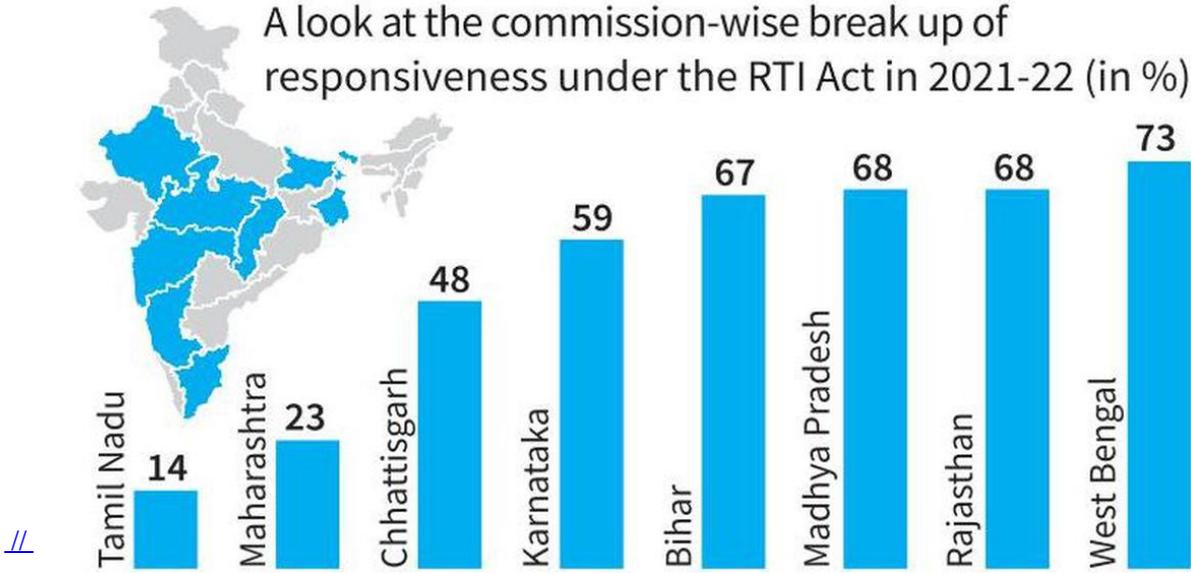
हाल ही में सतरक नागरकि संगठन (SNS) ने [सूचना का अधकिार \(Right to Information- RTI\) अधनियिम 2021-22](#) के तहत जवाबदेही रपिोर्ट कार्ड जारी कयि है, जो दर्शाता है कि त्तमलिनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जसिकी नपिटान दर 14% है ।

## प्रमुख बदि

- महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थति वाला राज्य है, जसिकी नपिटान दर 23% है ।
- इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर RTI आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की । इनमें **आंध्र प्रदेश, हरयिणा, झारखंड और पूरवोत्तर राज्य सकिक्मि, नगालैंड और त्रपिरा शामिल थे ।**
- बहिर राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC), जो वर्ष 2020 और 2021 में प्रकाशति आकलन के लयि RTI अधनियिम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने में वफिल रहा था, ने अपने प्रदर्शन में **काफी सुधार कयि और इसकी नपिटान दर 67% है ।**
- देश भर में बड़ी संख्या में **सूचना आयुक्तों ने बना कोई आदेश पारति कयि मामले वापस कर दयि थे ।**
  - उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शकियतों में से लगभग 40% को वापस कर दयि ।
  - 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बना कोई आदेश पारति कयि अपील या शकियत वापस कर दी थी ।
- **सूचना आयुक्तों के संदर्भ में प्रति आयुक्त नपिटान की दर बेहद कम है ।**
  - उदाहरण के लयि पश्चिम बंगाल के SIC के पास मामलों की वार्षकि औसत नपिटान दर प्रति आयुक्त 222 थी, जसिका अर्थ है कि प्रत्येक आयुक्त प्रभावी रूप से एक दिन में मुश्कलि से एक मामले का नपिटान कर रहा था । वैसे लंबति मामलों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी ।
- सभी 29 सूचना आयुक्तों में से केवल केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक वर्ष में प्रत्येक आयुक्त द्वारा नपिटाए जाने वाली अपीलों अथवा शकियतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया है ।

# Report card

A look at the commission-wise break up of responsiveness under the RTI Act in 2021-22 (in %)



## सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम:

### परिचय:

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिये नागरिकों के प्रश्नों के प्रति समयबद्ध जवाबदेही अनिवार्य बनाता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिये कार्य करना है।

### सूचना का अधिकार (संशोधन) विधियक, 2019

- इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये पद धारण करेंगे। इस संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 साल के लिये तय किया गया था।
- इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
  - इस संशोधन से पूर्व, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थीं एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें एक चुनाव आयुक्त (राज्यों के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त) के समान थीं।
- इसने मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिये पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण वेतन कटौती से संबंधित खंडों को समाप्त कर दिया, जो उन्हें उनकी सरकारी नौकरी के लिये प्राप्त हुए थे।
- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 की आलोचना कानून को कमजोर करने और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ देने के आधार पर की गई थी।

### कार्यान्वयन में समस्याएँ:

- सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रोएक्टिव डिसक्लोज़र में गैर-अनुपालन।
- नागरिकों के प्रति लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers-PIOs) का शत्रुतापूर्ण रवैया और सूचना छपाने के लिये सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करना।
- जनहति और नजिता के अधिकार के संबंध में स्पष्टता का अभाव।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव और खराब बुनियादी ढाँचा।
- सार्वजनिक महत्त्व के आवश्यक मामलों पर सक्रिय नागरिकों द्वारा किये गए सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति।
- RTI कार्यकर्ताओं और आवेदकों की आवाज़ दबाने के लिये उनके खिलाफ हमलों एवं धमकियों जैसे अन्य साधन।

## केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):

- स्थापना:** CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
- सदस्य:** इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं।
- नियुक्ति:** उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सफ़ारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिकष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- कार्यकाल:** मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर रह सकता है।

- वे पुनर्नयुक्तिके पात्र नहीं हैं।
- **CIC की शक्तियाँ और कार्य:**
  - आयोग का कर्तव्य है क्विह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कसी वषिय पर प्राप्त शकियतों के मामले में संबधति व्यक्ती से पूछताछ करे।
  - आयोग उचति आधार होने पर कसी भी मामले में स्वतः संज्ञान (Suo-Moto Power) लेते हुए जाँच का आदेश दे सकता है।
  - आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदिके संबध में सविलि कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।

## आगे की राह

- सूचना आयोगों का उचति कामकाज़ लोगों को सूचना के अधिकार का एहसास कराने के लयि महत्त्वपूर्ण है।
  - RTI कानून के तहत **सूचना आयोग अंतमि अपीलीय प्राधकिरण हैं** तथा लोगों के सूचना के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और सुवधि के लयि अनविर्य हैं।
- अधिकि प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लयि **पारदर्शति प्रहरी की तत्काल आवश्यकता** है।
- डजिटिल RTI पोर्टल (वेबसाइट या मोबाइल एप) अधिकि कुशल और नागरकि-अनुकूल सेवाएँ प्रदान कर सकता है जो परंपरागत मोड के माध्यम से संभव नहीं है।
  - यह पारदर्शति चाहने वालों और सरकार दोनों के लयि फायदेमंद होगा।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरकि सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, यह अनविर्य रूप से जवाबदेही की अवधारणा को फरि से परभाषति करता है। चर्चा कीजयि। (2018)

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/report-card-of-rti-responsiveness>

